

SHRI Y. B. CHAVAN : The question king is a different thing which will have gone into detail. But, you wanted to know in what way they wanted to make the aid that we are giving. Mostly food grant and commodity grant for export of miscellaneous commodities, materials and refined petroleum products. Then, there is the second commodity sterling loan, loan for the import of railway loan, loan, for the purchase of and aircraft, etc.

SHRI MAHAVIR TYAGI : How much of grant and how much of this is loan ? is the total ?

MR. CHAIRMAN : Mr. Tyagi, if you to put a question, I will call you later. Mr. Goray.

SHRI N. G. GORAY : Sir, in view of fact that the economy of India and the economy of Bangla Desh are in many respects complementary, has the Government seen that their plan is so evolved that it in with our plan and the two plans are complementary ? I do not mean we should trespass on their sovereignty anything like that. But, as in Europe, instance, so many countries have come here and evolved a sort of common economic policy. Like that, is there any apt to do that ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I think the honorable Member would appreciate that Bangla Desh has come into existence just and they have got their initial problem there is no question of dovetailing our with their plan. We have only offered experience in planning to them so that we can make use of that. But, beyond we are not doing anything.

MR. CHAIRMAN : Yes, Mr. Tyagi.

SHRI MAHAVIR TYAGI : Sir, I would like to know how much of this is given by way of grant and how much of is given by way of loan ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I think I would give this information. But, I feel I cannot give you the precise information on this at the present moment. Of course, there is an element of grant and there is an element of loan in it. But, the precise information I am unable to give you at the present moment.

MR. CHAIRMAN : Yes, you can give later. Mr. Anandan. This is the

SHRI T. V. ANANDAN : Sir, our country is the most philanthropic country and it is good that we are assisting Bangla Desh... (Interruptions)... This is a historical fact and it is there from the days of the Puranas. Sir, the economic condition in the country being so severe and the cost of living going up ...

MR. CHAIRMAN : Therefore you should put the question.

SHRI T. V. ANANDAN : ...taking into consideration the present situation in the country, is there any consideration for cancelling all the taxes that were imposed for assisting Bangla Desh ?

SHRI Y. B. CHAVAN : Whatever is our commitment, we shall certainly stand by it.

MR. CHAIRMAN : Yes, the next question please.

ANNUAL LEAVE TO MILITARY PERSONNEL

*182. SHRIMATI LAKSHMI KUMARI CHUNDAWAT :†
SHRIMATI SITA DEVI :
SHRI GANESH LAL MALI :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a fair percentage of officers and other ranks of the armed forces are not granted their entire annual leave of 60 days even during peace time;

(b) whether it is also a fact that the unavailed period of annual leave of the officers lapses with the expiry of the calendar year;

(c) whether the other ranks also cannot accumulate their leave beyond 90 days; and

(d) if so, whether any additional pay or allowances are admissible to officers and other ranks who are not permitted to avail of their annual/part annual leave; if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House :

†The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Lakshmi

STATEMENT

(a) Except where exigencies of service so require, every effort is made to grant the entire annual leave to which the Officers and OR are entitled.

Information regarding the percentage of officers and Other Ranks not granted their annual leave is not readily available; and time and labour involved in collection of this information will not be commensurate with the results likely to be achieved.

(b) Annual leave or balance thereof not commencing in the calendar year to which it pertains lapses. However, as a special case sanction was accorded to carry forward the unavailed annual leave for 1971 to 1972 or 1973 because most of the officers and other ranks of all three Services were not permitted to avail themselves of annual leave in 1971.

(c) Gorkha personnel of Nepalese domicile and subjects of Bhutan and Sikkim may avail of 120 days accumulated annual leave every alternate year; all Other Ranks serving in Indian Missions abroad may also accumulate annual leave up to 120 days.

(d) In the Central Government service, whether civil or military, there is no scheme to encash unavailed leave.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चंडावत : श्रीमन्, उनको छुट्टी एक्युमुलेट क्यों नहीं करने दी जाती और दी क्यों नहीं जाती है यह जबानी कह दें तो बेहतर है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उनकी छुट्टी इसलिए एक्युमुलेट नहीं की जाती है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे सैनिक और अफसर जो सेनाओं में काम करते हैं वे हर साल छुट्टी लें, इससे उनके स्वास्थ्य पर अच्छा असर होगा और उन्हें अपने परिवार और घरबार में रहने की सुविधा मिलती है। इसलिए हम चाहते हैं कि उन्हें हर साल छुट्टी लेनी चाहिए। केवल 71-72 में हमने उनको छुट्टी नहीं लेने दी थी। अब फिर से हमने उनको इजाजत दे दी है कि उस छुट्टी को 72-73 में ले सकते हैं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चंडावत : मेरा पहला प्रश्न यह है कि फ़ायर परसेटेंज आफ आफिसर्स

और सैनिकों को छुट्टी नहीं मिलती, अपने घर जाने के लिए उन्हें छुट्टी ही उपलब्ध नहीं होती और आप कहते हैं कि हर साल छुट्टी देते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम लोगों की सूचना यह है कि हम साधारणतः हर दम छुट्टी दे देते हैं बहुत ही कोई विशेष कारण हुआ, तब उनके शांति के समय छुट्टी नहीं दी जाती है, अन्यथा शांति के समय छुट्टी दी जाती है कभी अपवाद स्वरूप किसी केस में या किसी एक मामले में न दे जाय तो अलग बात है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चंडावत : समाप्ति सहोदय, मैं फिर जोर देकर कहती हूँ कि फ़ायर परसेटेंज को बराबर छुट्टी हर साल नहीं मिलती है अगर छुट्टी नहीं देते तो उनको मोनोटरी बेंनिफिट क्यों नहीं दिया जाता? मोनोटरी बेंनिफिट भी न मिलता, घर जाने के लिए छुट्टी भी नहीं मिलती।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि माननीय सदस्य के पास कोई ऐसा मामला है जिसमें छुट्टी नहीं गई शांति के समय तो वह हमें दे दें, मैं उसकी जाँच करवा लूँगा लेकिन यह बात अपवादस्वरूप होगी। साधारणतया ऐसा नहीं होता है।

जहाँ तक पैसे-रुपए का कम्पेन्सेशन देने का संबंध है, यह प्रक्रिया न तो हमारी सेनाओं में न हमारे यहाँ के जो असैनिक कर्मचारी हैं उन बीच में चलती है और चूँकि यह प्रक्रिया नहीं चल रही है इसलिए हम इसे शुरू भी नहीं करना चाहते

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चंडावत : क्यों करना चाहते?

श्री समापति : बस हो गया।

श्रीमती सीता देवी : क्या मंत्रीजी यह बात कि उन्होंने प्रश्न (ख) के जवाब में यह कहा है 1971 में जिनको छुट्टी नहीं मिली उन्हें 3 स्पेशली 1972-73 में इजाजत दी है, तो यह परमीशन केवल 1972-73 के लिए आगे भविष्य में भी वे सैनिक जो छुट्टी न ले सके उनको यह कंसेशन मिल सकेगा।

दूसरे (ग) में आपने यह जवाब दिया है कि नेपाली वंश के गोरखा और भूटान और सिक्किम के जो सैनिक हैं या विदेशों में जो भारतीय सैनिक हैं उनके लिए आपने यह परमीशन दी है कि उनको 120 दिन तक की छुट्टी मिल सकती है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि उनको आपने यह परमीशन दी है तो जो और सैनिक हैं उनके लिए यह सुविधा क्यों नहीं दी।

श्री विद्या चरण शुक्ल : सभापति महोदय, जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर मैं दे ही चुका हूँ कि जो 1971 में छुट्टी नहीं ले सके उन्हें 1972-73 में इस तरह की छुट्टी जोड़कर लेने की इजाजत दी जायगी। यह हमारा नियम है कि इस तरह की छुट्टी हम लोग साधारणतः नहीं देते हैं। फिर चूँकि 1971 में हमारे ऊपर आक्रमण की आशंका थी जिसके कारण हम ने कुछ लोगों को छुट्टी नहीं लेने देने दी थी, इस लिए हमने अमाधारण कार्य किया है जिसको हर साल करने का हम लोगों का इरादा नहीं है। जहाँ एक नेपालीज का सवाल है, आप जानते हैं कि इसमें केवल उन नेपालीज और गोरखों को सुविधा दी गई है जो कि नेपाल के रहने वाले हैं, भूटान और सिक्किम के रहने वाले हैं। ऐसे गोरखों को यह सुविधा नहीं दी गई है जो कि गोरखा होने के बावजूद भी हिन्दुस्तान के ही नागरिक है। इसी तरह की सुविधा हमने ऐसे कर्मचारियों को भी दी है जिनको हिन्दुस्तान के बाहर कार्यवश रहना पड़ता है। इस तरह की सुविधा साधारणतः हम उनको नहीं देते हैं जो कि हिन्दुस्तान के अन्दर रह कर के अपना कार्य करते हैं।

श्रीमती सविता बहन : मैं मिनिस्टर महोदय से सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि अक्सर देखा गया है कि जो युनिट्स होती हैं उनमें आफिसर्स कम होते हैं और जो ऐन्युअल लीव उन्हें ड्यू होती है, जो उन्हें मिलनी चाहिये, चूँकि बारी बारी आफिसर छुट्टी जाते हैं, इसलिए कई आफिसरों को वह छुट्टी उस साल में नहीं मिल पाती है, उनके लिए क्या आपने कोई ऐसा तरीका रखा है कि जो बेचारा घर से दूर रहकर के ड्यूटी देता है और साल में एक बार छुट्टी जाता है उसको वह छुट्टी जरूर मिले। मैं इस बात से सहमत हूँ कि वे छुट्टी में जायं क्योंकि वे छुट्टी इनज्वाय करते हैं, वहाँ रहते हैं,

बैठते हैं, लेकिन वह छुट्टी जरूर मिले, इस चीज को देखना चाहिये। क्या मिनिस्टर महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कौन से ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं जिनसे हर एक आफिसर को ऐन्युअल लीव पूरी तरह मिल सके।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैंने बताया, सभापति महोदय, कि हम लोग इस बात को देखते हैं और इस बात को पूरा करते हैं कि हर एक व्यक्ति को छुट्टी मिले। अगर कोई छुट्टी लेना न भी चाहे तो हम उससे कहते हैं कि यदि वह छुट्टी नहीं जायगा तो उसकी छुट्टी लैप्स हो जायगी। इस लिए समय-समय पर जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार हम छुट्टी देते हैं। एक साथ सब आफिसरों को हम छुट्टी नहीं दे सकते हैं। पर यह हमारा नियम है और नीति है कि हर एक आफिसर को, हर एक जवान को और हर एक नान कमीशंड आफिसर को हम छुट्टी देते हैं और इस तरह के हमने नियम बना रखे हैं कि उनको पूरी छुट्टी लेनी ही पड़ती है। हो सकता है कि एक आध को छुट्टी न दी हो, पर वैसे हर एक आफिसर, एक-एक जवान और हर एक नानकमिशनड आफिसर को हम लोग छुट्टी लेने के लिए लगभग बाध्य करते हैं।

ASSISTANCE FROM U. S. S. R.

*183. SHRI SASANKA SEKHAR SANYAL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what commercial, financial, technical and ancillary assistance and assistance in the shape of articles of consumption was obtained by India from U. S. S. R. in the years 1969, 1970 and 1971; and

(b) the value of such assistance in terms of Indian Currency ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) Machinery, equipment and technical services have been received under various Soviet Credit Agreements during 1969, 70 and 71, but no articles of consumption.

(b) Period	Soviet Credits (Rs. in millions)	
1969	541.5
1970	396.8
1971	160.2